

प्रेषक,

सुबर्द्धन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, देहरादून।

उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक ॥ फरवरी, 2013

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत अनुपूरक बजट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या:-6344/नियो0/जिला योजना/2012-13 दिनांक 05 फरवरी, 2013 तथा वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या:-321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012, 607/XXVII (1)/2013 दिनांक 1 जनवरी, 2013, 639/XXVII (1)/2013 दिनांक 4 जनवरी, 2013 व पूर्व में निर्गत स्वीकृति सम्बन्धी आदेश संख्या-858/XIV-1/2012 दिनांक 07 मई, 2012 तथा 1194/XIV-1/2012 दिनांक 24 जुलाई, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (टी0एस0पी0) हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित ₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।
 - (2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।
 - (3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 - (4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।
 - (5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवर्ल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
 - (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
 - (8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।
- 2- उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 :-321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और यह शासनादेश वित्त

विभाग के उक्त शासनादेश में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता आयोजनागत, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 04-अनुसूचित जनजाति कि सदस्यों को अंशकय हेतु अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्या:-3।5 (1)/XIV-1/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल।
3. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. जिला सहायक निबन्धक, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उपसचिव